संख्या १६२३/१०/5/7/35-आ0-2/2008-69

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

सचिव/प्रमुख सचिव (नाम से)
ग्राम्य विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, अम्बेडकर ग्राम विकास एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।

राज्य योजना आयोग-2 (नियोजन विभाग) — लखनऊ:दिनाँक:अप्रैल 15, 2010

महोदय,

योजना आयोग, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (Millenium Development Goals) को प्राप्त करने हेतु संयुक्त कन्वर्जेन्स कार्यक्रम प्रदेश के 05 जनपदों (आज़मगढ़, बदायूँ, हरदोई, हमीरपुर एवं सोनभद्र) में क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह कार्यक्रम देश के कुल 07 राज्यों के 35 जनपदों में लागू है।

इस कार्यक्रम का लक्ष्य मुख्य विकास कार्यक्रमों यथा-सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, एकीकृत बाल विकास सेवायें, ग्रामीण पेयजल, मध्यान्ह भोजन, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि आदि को अपेक्षित गति प्रदान करना तथा जनपद स्तर पर गवर्नेन्स को मजबूत करना है ताकि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग एवं परिणामी सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। इसके लिये कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी की क्षमता में वृद्धि तथा अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रस्तावित है। सामाजिक क्षेत्र में क्रियान्वित योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण तथा परिणामों को प्राप्त करने में यह कार्यक्रम सहायक होगा और इससे प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने में भी सहायता मिलेगी। कार्यक्रम के विवरण तथा मुख्य बिन्दु संलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

इस सम्बन्ध में सुलभ सन्दर्भ हेतु भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र तथा राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षरित Memorandum of Understanding (MOU) भी संलग्न है जिसमें सभी हितग्राही (Stakeholders) के दायित्व एवं अन्य

विवरण उल्लिखित है(संलग्नक-2)। इस कार्यक्रम के सुचारू रूप से क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा समन्वय के लिये राज्य स्तर पर नियोजन विभाग नोडल विभाग होगा। श्रीमती मृदुला सिंह, अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद, नियोजन विभाग राज्य स्तर पर (संलग्नक-3) तथा मुख्य विकास अधिकारी जनपद स्तर पर कार्यक्रम हेतु नोडल अधिकारी होंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव संसाधन के रूप में प्रत्येक जनपद में एक डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर तथा यू0एन0 वालेन्टीयर तैनात किये जायेंगे, जो कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहभागी होंगे।

कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा राज्य स्तर पर परिणामों (Deliverables) को प्राप्त करने के लिये आपसे अपेक्षा है कि MOU के पृष्ठ;5 पर चिन्हित बिन्दु-6 के आधार पर अपने राज्य तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों को निम्नलिखित रूप से सहयोग देने के लिये यथावत् निर्देशित करें:-

1. भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के विश्लेषण हेतु राज्य व जिला स्तर पर आँकड़े, रिपोर्ट तथा प्राप्त संसाधनों एवं व्यय की सूचना समय से उपलब्ध कराना।
2. राज्य व जनपद स्तर पर मानव विकास सूचकांकों के विश्लेषण के लिये समय-समय पर आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये संयुक्त अनुश्रवण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना।
4. विकास कार्यक्रमों हेतु जनपद स्तर पर गठित समस्त समितियों एवं कार्यक्रम नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु समस्त विभागीय बैठकों में कन्वर्जन्स कार्यक्रम के महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद में उपलब्ध यू0एन0 टीम को शामिल करना।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या:623/10(1)/5/7/35-आ0-2/2008-69, तद् दिनाँक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी-का-तालाब, लखनऊ।
4. यूनाईटेड नेशन्स रैजीडेन्ट को-आर्डिनेटर, यू0एन0आर0सी0ओ0, नई दिल्ली।
5. राज्य प्रतिनिधि, यूनीसैफ, लखनऊ।
6. हेड, गवर्नेन्स यूनिट, यू0एन0डी0पी0, नई दिल्ली।
7. नेशनल प्रोग्राम आफिसर, यू0एन0एफ0पी0ए0, नई दिल्ली।
8. राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वयक, कन्वर्जेन्स कार्यक्रम, नई दिल्ली।
9. अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद, राज्य योजना आयोग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(जे0एन0 चैम्बर)
प्रमुख सचिव